

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin Singh Bhadauria I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 37-8-18 at time 1:30 P.M. at Almora in which application claiming rights of **Quarban** area measuring **3.850** hec. for the कोटिला—गवाड़ मोटर मार्ग से सुरईखेत तक मिलान of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dwarahat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

DATE:

विधि समाज कल्याण विधिकारी

संसदीय

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

निलंबित
अल्मोड़ा।

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.850 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of कोटिला—गवाड मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान **district Almora within jurisdiction of gawan, kotila, Bayela, Faldwadi, Walana and Talli bitholi Village (s) in Dwarahat tahsils.**

It is further certified that:

- (d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **3.850** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:YES
- (f) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:YES

Encl: As above

प्रधान अमाज कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड

District Collector,
उत्तराखण्ड।

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recantation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 3.850 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of कोटिला—गवाड सोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान district Almora within jurisdiction of gawan, kotila, Bayela, Faldwadi, Walana and Talli bitholi Village (s) in Dwarahat tahsils.

It is further certified that:

- (g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 3.850 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (i) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Quarban villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (j) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (k) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (l) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

पिंडा दस्तावेज कल्पना विभाग
मृत्यु

Nitin Singh Bhadauria
District Collector Almora

बिला अधिकारी
बलमोदा.

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

**कार्यालय उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, द्वाराहाट**

उपखण्ड द्वाराहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत 3.850 हेक्टर वन भूमि) का लोगोनिवारी रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील द्वाराहाट) की दिनांक ६/११/८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री २३। अ। अ। सौ. उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1— श्री २३। अ। अ। सौ. उपजिलाधिकारी ए। अध्यक्ष
- 2— श्री ए। अ। अ। सौ. उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3— श्री ए। अ। अ। सौ. सहायक समाज कल्याण अधिकारी ए। अ। सौ. सदस्य / सचिव
- 4— श्री ए। अ। अ। सौ. बी। अ। अ। सौ. क्षेत्र ए। अ। अ। सौ. सदस्य ए। अ। अ। सौ. सचिव
- 5— श्रीमती प्रद्युम्ना बिल्लू बी। अ। अ। सौ. क्षेत्र ए। अ। अ। सौ. सदस्य ए। अ। अ। सौ. सचिव

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान निर्माण खण्ड, लोगोनिवारी, रानीखेत के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड द्वाराहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान परियोजना के निर्माण हेतु 3.850 हेक्टर वन भूमि निर्माण खण्ड, लोगोनिवारी, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.....
जनपद.....

उप जिलाधिकारी
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —ग्वाड़
तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हेठो आरक्षित वन भूमि 3.133 हेठो सिविल सोयम भूमि 0.437 हेठो वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.850 हेठो वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वाड़ द्वारा दिनांक 13/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरित्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

ग्वाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हेठो/
ग्राम सचिव

मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ग्वाड़
चौथो नं.
मुहर

हेठो/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित द्वाराहाट

प्रपत्र-23.1

दिनांक 13/07/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गावाड

क्रम सं.

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

- (1) मुनी पाण्डे
- (2) मोहन सिंह
- (3) नवीन पाण्डे
- (4) केलाराज चड्डे
- (5) जीत सिंह
- (6) कमला देवी
- (7) न-दी देवी
- (8) गोपाल सिंह
- (9) भोला राम
- (10) जीरीश राम
- (11) लक्ष्म राम
- (12) छरीश राम
- (13) चन्दन राम
- (14) सुरेश चड्डे
- (15) चन्द्रपुर कुमार
- (16) दिवान राम
- (17) हर सिंह
- (18) अनोज सिंह
- (19) दिवान सिंह
- (20) हरश पाण्डे
- (21) सलोष राम
- (22) नवीन राम
- (23) पंकज कुमार
- (24) हरमन सिंह
- (25) जाको देवी
- (26) कमला पाण्डे
- (27) शुशीला पाण्डे
- (28) रमेश चड्डे पाण्डे
- (29) जीरीश पाण्डे
- (30) मनोज पाण्डे

जीत सिंह
कमला देवी
न-दी देवी
गोपाल सिंह
भोला राम

प्रोला राम

ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत गावाड
प्रधान द्वारा दिलाई गया है

मुनीपाण्डे
Mohan Singh
नवीनपाण्डे
केलाराजचड्डे
जीतसिंह
कमलादेवी
न-दीदेवी
गोपालसिंह
भोलाराम
प्रोलाराम
जीरीशराम
लक्ष्मराम
छरीशराम
चन्दनराम
सुरेशचड्डे
चन्द्रपुरकुमार
दिवानराम
हरसिंह
अनोजसिंह
दिवानसिंह
नीरोजसिंह
लक्ष्मसिंह
छरीशराम
चन्दनराम
सुरेशपाण्डे
दिवानराम
हरमनसिंह
जाकोदेवी
कमलापाण्डे
शुशीलापाण्डे
रमेशचड्डेपाण्डे
जीरीशपाण्डे
मनोजपाण्डे

Santosh Singh
Anil Singh
Pankaj Kumar

जीतपाण्डे
Renuka Raut
शुशीलापाण्डे
रमेशचड्डेपाण्डे
जीरीशचड्डेपाण्डे
MK Pandey

प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम —कोटिला
तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हेठो आरक्षित वन भूमि 3.133 हेठो सिविल सोयम भूमि 0.437 हेठो वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.850 हेठो वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटिला द्वारा दिनांक 4-8-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

कोटिला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हो/
ग्राम सचिव

मुहर सहित

Devi Ram
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोटिला
विंख्या द्वाराहाट
जिला अल्मोड़ा

हो/
ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

2021/01/24
प्रधान
ग्राम पंचायत कोटिला
विंख्या द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 4-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हरताक्षर

- ① भूमि स्टेटीक सिएट
 - ② अपालटिंग
 - ③ यात्रा ट्रैड
 - ④ जीवन स्टी
 - ⑤ मदल सिएट
 - ⑥ कुनून सिएट
 - 7 जमन सिएट
 - 8 राग्ड सिएट
 - 9 - डोरेश्वर सिएट
 - 10 - बोहोंड सिएट
 - 11 - गोपाल सिएट
 - 12 चंद्रीज
 - 13 जस्ता नाम डायेक्टरी
 - 14 वृष्टि सिएट
 - 15 वारोउरी
 - 16 - गोपाल सिएट
 - 17 - फेस्टिवल सिएट

ग्राम प्रधान

रायाल्डर न

प्रधान

प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —कोटिला
तहसील दुर्गापुर जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280) 0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हेतु सिविल सोयम भूमि 0.437 हेतु वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 3.850 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटिला द्वारा दिनांक 4/8/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्णन चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हेतु/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित

हेतु/ ग्राम प्रधान/ सरपंच
मुहर सहित

ग्राम पंचायत बघेला
पो० ओ० चन्थरिया
क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.1

दिनांक ४/८/१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
०१	जसराम	जसराम
०२	वन्दनराम	वन्दनराम
०३	मनोवरराम	मनोवरराम
०४	पुष्पेन्द्र नाला	पुष्पेन्द्र नाला
०५	दिव्यालय	दिव्यालय

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत ब्येला
पो० ओ० चन्द्ररिया
दिव्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — कोटिला
तहसील कोटिला जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हेठो आरक्षित वन भूमि 3.133 हेठो सिविल सोयम भूमि 0.437 हेठो वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.850 हेठो वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटिला द्वारा दिनांक 03.02.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

पंकजी चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

Panchayat Member
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
हेठो पंचायत मासिला
ग्राम सचिव मासिला
हेठो मासिला
मुहर सहित

Panchayat Member
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मासिला
हेठो मासिला
मुहर सहित

विधान सभा
ग्राम पंचायत प्रधान
लो०खण्ड द्वाराहाट
हेठो/
ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

प्रपत्र-23.1

दिनांक ०३.७.२०१० को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

लिखित पत्र

ग्राम पंचायत फॉर्म
विधायक सभा पत्र

ग्राम प्रधान

लाली देवी
मिशनी देवी

बिल्ही देवी

देवी देवी
कुमार चंद्र

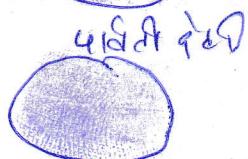
मिशनी देवी

कुमार चंद्र

मिशनी देवी

मिशनी देवी

मिशनी



इयान चंद्र

Seed

Rice



कमला चंद्र
विनीता पाट



प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम —बलना
तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बलना द्वारा दिनांक 4-8-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बलना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हे0/

ग्राम सचिव

मुहर सहित
द्वाराहाट
ग्राम पंचायत नगर समिक्षा अधिकारी
ग्राम पंचायत बलना
०६० द्वाराहाट
जिला अल्मोड़ा

हे0/

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

30/04/2018
ग्राम पंचायत नगर समिक्षा अधिकारी
ग्राम पंचायत नगर समिक्षा अधिकारी
ग्राम पंचायत नगर समिक्षा अधिकारी

प्रपत्र-23.1

दिनांक 4-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1. रमेश कुमार

2. लक्ष्मी कुमार

3. दामोदर

4. वार्षिक

5. जीवा देवी

6. कमला देवी

7. सुनीला देवी

8. गोपाल कुमार

9. चंद्रनाथ

10. नंदी देवी

11. सुखली देवी

12. एवीश्वर

13. वल्लभा देवी

14. अरुणा

15. लक्ष्मी बहादुर

16. हेमा देवी

17. आलधु

<img alt

प्रपत्र-23.1

दिनांक 4-8-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत किठोली भाली

क्रम सं.

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

नाम

नाम

- 1 फराहा चन्द्र
- 2 गोपल लिलू
- 3 जगदीश लिलू
- 4 राम लिलू
- 5 राम लिलू
- 6 लक्ष्मी लिलू जसोदासंद
- 7 दिलीप
- 8 हीरा लिलू
- 9 राम लिलू
- 10 राम लिलू
- 11 लाल लिलू
- 12 लाल लिलू
- 13 लाल लिलू
- 14 लाल लिलू
- 15 लाल लिलू
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 34
- 23

Shiv
Jagadish Singh
Ram
Ram
Lata
Rama
Rama
Suresh
Rama
Rama

ग्राम प्रधान

मोहनीदीबी
नान,
ग्राम पंचायत गस्ती-बिठोली
पो. ओ. ओ. बिठोली
पो. ओ. शारदापाट (वल्लोक)

प्रारूप—30.3

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला
गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम - मल्ली लिठोली (सुरक्षित)
तहसील डाकाट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला गवाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान हेतु (0.280हे0 आरक्षित वन भूमि 3.133 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.437 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.850 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नियमित द्वारा दिनांक 4-8-19 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लोगोनियोवित, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रामाणी विटोली चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०निर्विठ०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह० /

ग्राम सचिव

मूहर सहित

प्राम पंचायत अधिकारी
 प्राम पंचायत
 विनियंत्रण
 चला

ह० /

ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित पा० श० बिठोली
पा० श० शारदाट (बहुतों)